(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Karnataka	2041	2263	2281	2423	2501
11.	Kerala	1815	1826	1932	2043	2113
12.	Madhya Pradesh	1698	1539	1620	1766	1738
13.	Maharashtra	3456	3357	3734	3980	4157
14.	Manipur	1739	1842	1890	1921	—
15.	Meghalaya	1735	1759	1612	1698	1835
16.	Nagaland	1891	1900	—	—	—
17.	Orissa	1383	1530	1476	1542	1581
18.	Punjab	3737	3841	3932	4053	4167
19.	Rajasthan	1942	1773	1934	1760	2016
20.	Sikkim	3369	3492	—	—	—
21.	Tamil Nadu	2275	2311	2405	2498	2656
22.	Tripura	1667	1689	1713	—	—
23.	Uttar Pradesh	1652	1626	1618	1638	1663
24.	West Bengal	2105	2187	2241	2323	2434

Q: Quick Estimates P: Provisional

— Not made available by the concerned State Governments.

Source: Central Statistical Organisation

Note: The State of Mizorom prepare these estimates at Current prices only.

DDA Flats Remaining Unoocupied

472. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of DDA flats, with localities, which have since been allotted but have not been occupied by the allottees during the last three years; and

(b) what are the reasons for these houses/flats remaining unoccupied?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) D.D.A. has reported that in about 630 cases, where payments have been made by the concerned individuals for the flats allotted to them, possession letters to occupy the flats at site have not been issued because of non-availability of electricity. These flats are unoccupied and arc mainly located "io Dwarka, Rohini, Kondli, Gharoli and Narela.

नई विद्युत नीति

473. श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई विद्युत-नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी विदेशी तथा निजी कम्पनियां शामिल हैं;

(ग) क्या इस नीति को लागू कर दिया गया है; यदि नहीं तो इसे कब तक लागू किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई विलम्ब है तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) बदलती हुई आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विद्युत नीति में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र में विद्युत

परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारतीय एवं विदेशी कंपनियों से 194 अभिरूचियों के प्रस्ताव प्राप्त किए गए है। निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं, जो क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	परियोजना/प्रवर्तक का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)*
1.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रिज	216	816.00
2.	गोदावरी जीबीपीपी मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नालॉजी	208	748.43
3.	डाभोल सीसीजीटी मैसर्स डाभोल पावर कंपनी	695 (फेज-1)	2912.00
4.	बसप्पा एचईपी जयप्रकाश इंडस्ट्रिज लि०	300	949.23
5.	हजीरा सीसीपीपी मैसर्स एस्सार पावर लि०	515	1666.56
6.	पगुथन जीबीपीपी मैसर्स गुजरात टोरंट एनर्जी कारपोरेशन	655	2298.14
7.	महेश्वर एचईपी मैसर्स एस० कुमार्स लि०	400	1073.00
8.	तवा एचईपी मैसर्स हिन्दुस्तान इलेक्ट्रोग्राफिक्स लि०	12	65.00
9.	बड़ोदा सीसीजीटी मैसर्स जीआईपीसीएल	167	341.13
10.	जोजोबेरा टीपीपी मैसर्स जमशेदपुर पावर कंपनी लि०	202.5	981.00
11.	आदमटीला जीबीपीपी मैसर्स टीएलएफ पावर लि०	9	40.00
12.	बनासकांडी जीबीपीपी मैसर्स डीएलएफ पावर लि०	151.5	70.00

* जहां राज्य/प्रवर्तक द्वारा अनंतिम लागत अनुमान नहीं दिए गए है, वहां पूंजीगत लागत 3.5 करोड़ रु०/मे०वा० कल्पित की गयी है।

(घ) अधिकतर निजी प्रवर्त्तकों द्वारा अभी निवेश लिंकेजों को अंतिम रूप दिया जाना है और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना है।

Project .to Produce Petroleum from Plants

474. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of SCIENCE AND TECHOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Institute of Petroleum, Dehradun and the National Botanical Research Institute, Lucknow have started a project to produce petroleunf from certain plants known as Petrol-Plants; and

(b) if so, the details thereof and the progress made so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes, Sir. Indian Institute of Petroleum (IIP), Dehradun and National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow had undertaken in 1979 a project on introduction, screening and cultivation of potential pctro-crops and their conversion to petroleum hydrocarbons.

(b) The project was initiated with funding from Department of Non-Conventional Energy Sources, Government of India. The project was carried out in three phases each phase